इकाई 14 दो विश्व युद्ध*

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 युद्धों के कारक

14.2.1 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं और राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता

14.2.2 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और खेमों की स्थापना

14.3 विश्व युद्धों में हिस्सा लेने वाले राष्ट्र

14.4 आपसी टकराव वाली विचारधाराओं के रूप में युद्ध

14.4.1 दो विश्व युद्धों के दौरान विचारधाराओं द्वारा परिभाषित सशस्त्र खेमे

14.4.2 युद्ध की शुरुआत के समय यूरोप का राजनैतिक परिदृश्य

14.5 शीत युद्ध की शुरुआत

14.6 सारांश

14.7 शब्दावली

14.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- औद्योगीकरण के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में आए बदलावों को रेखांकित कर सकेंगे,
- एकल, अबाधित प्रक्रिया के रूप में दो विश्व युद्धों के बीच की निरंतरता को समझ सकेंगे, और
- विचारधारात्मक आधारों पर खेमों में विभाजित समूहों के बारे में जान सकेंगे जो दोनों युद्धों में लगभग समान थे।

14.1 प्रस्तावना

अभी तक हमने औद्योगिक पूँजीवाद की प्रकृति और परिणामों तथा आधुनिक राजनीति के उद्भव पर विचार किया है। इसके पहले की इकाइयों में हम राष्ट्र-राज्यों के उद्भव और साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति का अध्ययन कर चुके हैं। हम समझते हैं कि अब आप यह समझने की स्थिति में होंगे कि कैसे इन विविध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप दो विश्व युद्ध लड़े गए। औद्योगीकरण से नए राज्यों का उद्भव हुआ और वे पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लड़ने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विताओं का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का कोई तंत्र मौजूद न होने के कारण पूरी दुनिया में सशस्त्र युद्ध अपरिहार्य हो गया। चूंकि यूरोप विचारधारात्मक खेमों में बंट चुका था, अतः यह युद्ध ने भी वैचारिक आयाम ग्रहण कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध में विचारधारा अभी पृष्ठभूमि में थी परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में

*प्रो. श्री कृष्णा (रिटायर्ड), डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, रेवाड़ी, हरियाणा

निश्चित रूप से उदारवादी जनतंत्र और समाजवाद एकजुट हुए और उन्होंने दक्षिणपंथी निरंकुश शासनों का विरोध किया। विडंबना यह है कि युद्ध ने दूसरे खेमे के विनाश का कोई समाधान पूरा नहीं किया। सशस्त्र टकराव के बाद शीत युद्ध का युग आरंभ हो गया।

14.2 युद्धों के कारक

इन दो युद्धों के लिए कई कारक उत्तरदायी थे। इस शताब्दी के आरंभ में अलग-अलग विचारधाराओं के आधार पर विश्व प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय ताकतों में विभाजित हो गया। ये सभी ताकतें आधुनिक युद्ध के हथियारों से युक्त थीं। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में उन्होंने पूरे विश्व पर वर्चस्व जमाने के लिए प्रतिद्वंद्विता आरंभ की। इनके इस टकराव और प्रतिद्वंद्विता को सुलझाने के लिए कोई शांतिपूर्ण तरीका मौजूद नहीं था इसलिए दो विश्व युद्ध लड़े गए। आइए, इस पर विस्तार से विचार करें।

14.2.1 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं और राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता

औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में मूलभूत परिवर्तन आया। राष्ट्र-राज्यों के उद्‌भव और औद्योगिक संसाधनों में हुई वृद्धि के कारण बड़े पैमाने पर राज्य ने मानवीय और भौतिक संसाधन जुटाए और इससे उन्होंने लड़ने की शक्ति अर्जित की। उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में औद्योगिक-उत्पादन तकनीक का इंग्लैंड के बाहर प्रसार हुआ तथा बेल्जियम (1815-30), स्वीडेन, फ्रांस, अमेरिका और प्रशा (1840-60), नौर्वे, रूस और जापान (1870-90) जैसे अनेक राज्यों में यह तकनीक प्रचलित हुई। धीरे-धीरे इन औद्योगिक विकासों के परिणामस्वरूप एक व्यापक टकराव की ऐसी संभावना बनने लगी जो आज तक वास्तविकता का रूप नहीं ले पाई थी। आगे आने वाले भागों में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औद्योगीकरण के क्षेत्र में देर से प्रवेश करने वाले देशों ने पूँजी बाजारों से संबंधित नए पहलुओं जैसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों तथा व्यापार संगठन के नए पहलुओं जैसे संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, जिनकी सीमित जिम्मेदारी थी, और संरक्षणवाद तथा प्रोत्साहन की राज्य की सक्रिय नीति जैसे पहलुओं का उपयोग किया। रेलवे के प्रसार ने पूरी दुनिया को एक अर्थव्यवस्था के सूत्र में बांध दिया। हालांकि अभी भी यह प्रौद्योगिकी वाष्प और कोयले पर आधारित थी परंतु बिजली उत्पादन और रासायनिक तकनीक तथा तेल उद्योग ने इस युग में काफी प्रगति की। 1880 के दशक के बाद औद्योगिक और औद्योगीकृत देशों का आर्थिक विकास काफी तेज हुआ। बिजली उत्पादन की नई प्रौद्योगिकियों के कारण उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। उत्पादन की नई तकनीकों के कारण नए उत्पाद (जैसे आटोमोबाइल) सामने आए। हालांकि ब्रिटेन सबसे प्रभावी शक्ति बना रहा परंतु अमेरीकी और जर्मन अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के कारण स्थिति बदलने लगी और 1880 के दशक के बाद से इंग्लैंड की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होने लगी। मेजी पुनर्स्थापना (1868) के बाद जापान की उन्नति और रूस के औद्योगीकरण से विश्व का आर्थिक माहौल और भी बदल गया। औद्योगीकरण के तेजी से फैलने के कारण कोयले की ऊर्जा का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। यहाँ तक कि 1913 में कोयले से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में पूरी दुनिया की 90% ऊर्जा प्राप्त की जाती थी लेकिन 1880 के दशक से खासकर अमेरीका में विद्युत ऊर्जा धीरे-धीरे महत्वपूर्ण हो गई। अमेरिकी और जर्मन कम्पनियां या फर्म ब्रिटिश उत्पादनकर्ताओं से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा करने लगी। उद्योग के रासायनिक और विद्युत क्षेत्रों में उनके पास श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी उपलब्ध थी। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य के आसपास ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, खासकर रेलवे के विकास के लिए, दीर्घ अवधि वित्त की आपूर्ति करने वाले बैंकर की भूमिका निभा रही थी। अतएव यूरोप के अन्य दो प्रतिस्पर्द्धियों– फ्रांसीसियों और जर्मनों– ने यूरोप की परिधि पर स्थित औद्योगीकृत राष्ट्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

1890 के दशक के बाद और खासकर 1900 के दशक के बाद फ्रांस और जर्मनी द्वारा विदेशी निवेश पूरी दुनिया में किया जाने लगा जैसे अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, रूस और चीन। इन आर्थिक विकासों के परिणामस्वरूप यूरोप में कई आर्थिक-राजनैतिक शक्ति केंद्रों का उद्‌भव हुआ। ये ताकतें एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थीं और विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन के वर्चस्व को चुनौती दे रही थीं।

बढ़ता औद्योगीकरण अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का कारण बना रहा और इससे एक संकट भी उत्पन्न हुआ। वस्तुतः अभी भी 'राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं' के बीच प्रतिस्पर्द्धा के रूप में पूँजीवाद की विश्व व्यवस्था मौजूदा थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यह प्रवृत्ति ठोस रूप लेने लगी। औद्योगीकरण के क्षेत्र में देर से आने वाले (जैसे प्रशा, रूस और जापान) भी 'राष्ट्रीय क्षेत्रों' के बाहर भी अपना दावा करने लगे। अब आर्थिक और राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता सैद्धांतिक गठबंधनों का रूप लेने लगी। हालांकि ये संघटन काफी ढीले-ढाले थे। 1893 में स्थापित अखिल जर्मन लीग में दक्षिणपंथी संकीर्णवादी ताकतों का वर्चस्व था जो मध्य यूरोप (*मितेलयूरोपा*) पर आर्थिक और क्षेत्रीय आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। वे बेल्जियम, फ्रांसीसी जिले लौंगवी-ब्री जहाँ कच्चा लोहा पाया जाता था, सोम तक जाने वाला फ्रांसीसी तटीय प्रदेश, ट्यूलोन स्थित भूमध्यसागरीय अड्डे के साथ-साथ पोलैंड और बाल्टिक राज्यों पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। उन्होंने जर्मनी के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया-हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, नीदरलैंड, स्वीटजरलैंड, डेनमार्क, स्वीडेन, नौर्वे और फिनलैंड के साथ-साथ जर्मन, फ्रांसीसी और बेल्जियम उपनिवेशों को शामिल कर एक मध्य यूरोपीय परिसंघ बनाने की भी परिकल्पना की। मई 1915 में केंद्रीय जर्मन उद्योग परिसंघ और अन्य औद्योगिक तथा कृषीय हितों ने भी इन योजनाओं को अपना समर्थन दिया। यह अकस्मात नहीं था कि युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा समर्थित गठबंधनों तथा बुखारेस्ट तथा ब्रेस्ट-लिटोवस्क (1918) की संधियों ने काफी हद तक जर्मन सपने को साकार किया। हिटलर केवल ऑस्ट्रिया के साथ संघ (ऐन्शलस) ही नहीं बनाना चाहता था बल्कि वह जर्मनवासियों के लिए पर्याप्त जीवन-स्थल (लेबेन्सरोम) भी चाहता था।

इसी प्रकार इतालवी दक्षिणपंथ 'प्रोलेटेरियन' (सर्वहारा) और प्लुटोक्रैटिक (समर्थ) की वर्ग संबंधी अवधारणाओं का उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को पुनः परिभाषित करने और 'सर्वहारा' इटली के लिए उपनिवेशों की माँग करने के लिए किया। इसी प्रकार जापान में दक्षिणपंथी गरम दल राष्ट्रवादियों (ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी 1901), अम्पायर फाउंडेशन सोसाइटी (1926) और जापान प्रोडक्शन पार्टी (1931), ने "विश्व संसाधनों के समतावादी वितरण" की माँग की। यहाँ तक कि उन्होंने जापान के नेतृत्व में पूरब में 'एक सह-समृद्धि क्षेत्र' बनाने के लिए सैन्य कार्यवाई का भी समर्थन किया।

14.2.2 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और खेमों की स्थापना

औद्योगीकरण के कारण शक्ति के कई केंद्र बन गए और इसके कारण दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए नए दावेदार दौड़ में शामिल हो गए। विभिन्न प्रतिद्वंद्वियों के दावों को निपटाने या टकरावों को सुलझाने का कोई प्रणाली मौजूद नहीं था। टकरावों को सुझाने के दिशाहीन प्रयास किए गए। प्रथम और द्वितीय हेग सम्मेलनों (1899 और 1907) में हथियारों में कमी लाने का असफल प्रयत्न किया गया। अन्तर-राज्य टकरावों को रोकने के लिए हेग में स्थापित मध्यस्थता न्यायालय भी अशक्त और बेकार साबित हुआ। बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा। इस युद्ध की संभावना को देखते हुए यूरोपीय शक्तियों के बीच हथियारों की तथा सैन्य शक्ति बढ़ाने की होड़ हो गई। अपनी-अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं (कमजोर) के संरक्षण के लिए की जा रही सैन्य तैयारियों को जनता का अच्छा समर्थन मिला। यूरोपीय शक्तियों ने सुरक्षा उपायों के तहत जो सैन्य गठबंधन किए थे उनसे यह

स्पष्ट था कि यदि युद्ध छिड़ा तो इसके केवल दो ही देश शामिल नहीं होंगे बल्कि उनसे जुड़े सभी देश इससे प्रभावित होंगे। इस प्रकार के गठबंधन से एक देश को एक ऐसे 'शत्रु' के खिलाफ युद्ध करना पड़ सकता था जिससे उसकी सीधी दुश्मनी नहीं थी। इन गठबंधनों की शर्तों के गुप्त रखे जाने के भी गंभीर विनाशकारी परिणाम हुए। 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हंगरी ने यह समझौता किया कि रूस द्वारा आक्रमण किए जाने पर वे मिलकर उसका सामना करेंगे। 1882 में इटली भी समझोते में शामिल हो गया और इसे त्रिपक्षीय गठबंधन के नाम से जाना गया। 1894 में फ्रांस और रूस ने आपस में समझौता किया कि यदि त्रिपक्षीय गठबंधन में सम्मिलित कोई देश सेना की लामबंदी करता है तो वे भी अपनी सेना को युद्ध के लिए लामबंद करेंगे। उन्होंने यह भी समझौता किया कि जर्मनी द्वारा आक्रमण किए जाने पर वे मिलकर उनका सामना करेंगे। 1904 में जर्मनी द्वारा नौसैन्य शक्ति के बढ़ाए जाने के कारण ब्रिटेन ने अपनी "गौरवशाली अलगाव" की नीति को त्याग दिया। ब्रिटेन ने न केवल फ्रांस के साथ उपनिवेश संबंधी पुराने मतभेदों को सुलझा लिया बल्कि उसके साथ *ऑन्टान्ट कौर्डिएले* (मित्रतापूर्ण समझौता) पर हस्ताक्षर भी किए। हालांकि इस समझौते में सैन्य समर्थन की कोई बात नहीं थी परंतु दोनों देशों ने संयुक्त सेना योजनाओं पर विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया। 1907 में रूस भी *ऑन्टान्ट कौर्डिएले* में शामिल हो गया और इसे *ट्रिपल ऑन्टान्ट* के नाम से जाना जाने लगा। इन समझौतों से यूरोप दो प्रतिद्वंद्वी खेमों में बंट गया।

भूमंडलीय वर्चस्व के प्रश्न को निपटाने के लिए इन दोनों खेमों के बीच 1914-1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। संधियों (वर्साय, रिगा, लाउसेन, लोकार्नो आदि) के कारण यूरोप का नक्शा परिवर्तित हो गया। रूसी रोमानोव, होहेनजौलर्न, हैब्सबर्ग और औटोमन जैसे चार बड़े साम्राज्य पराजित हुए और उनका पतन हो गया। साम्यवादी शासन की स्थापना के पहले रूस में खून खराबे से युक्त गृह युद्ध हुआ। जर्मनी एक गणतंत्र बन गया तथा उसे पराजय का अपमान सहना पड़ा और वह विरोधी खेमे की क्षतिपूर्ति के बोझ के तले दब गया। विजयी पश्चिमी जनतंत्रों को अनेक क्षेत्र प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए, फ्रांस को अल्सास-लौरेन प्राप्त हुआ जो 1871 से जर्मनी के पास था। ब्रिटेन को और ज्यादा औपनिवेशिक क्षेत्र मिले परंतु उसके साम्राज्य की सुरक्षा पर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे। वस्तुतः इतने बड़े पैमाने पर हुए युद्ध के बावजूद विश्व स्तर पर वर्चस्व की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। 1922 में ब्रिटेन को मजबूरन अमेरिका के साथ नौसैनिक समानता को स्वीकार करना पड़ा और आंग्ल-जापानी समझौता त्याग देना पड़ा जो उनके सुदूरपूर्व साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी था। इटली और जापान को जो क्षेत्र प्राप्त हुए थे, उससे वे संतुष्ट नहीं थे। फ्रांस, ब्रिटेन ने शांति के लिए जो कड़ी शर्तें रखी थीं और जो नई सीमाएं निर्धारित की थीं उसमें भविष्य के टकराव की अपार संभावनाएं थीं।

अमेरीकी राष्ट्रपति वुडरो विलसन ने पूरे विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए विश्व संगठन का विचार सामने रखा परंतु उसे इसमें खास सफलता नहीं मिली क्योंकि लीग ऑफ नेशन्स जो कि वर्साय की संधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था को अमेरीका की भी मंजूरी नहीं मिली। इसके अलावा पराजित ताकतों को भी इसमें सदस्य नहीं बनाया गया। जर्मनी को 1926 में लीग में शामिल होने की अनुमति दी गई। 1921 और 1930 में नौसैनिक निरस्त्रीकरण में आंशिक सफलता मिली जब ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ने अपने कुछ युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की संख्या कम करने का समझौता किया परंतु जेनेवा में सम्पन्न हुए (1932-34) लीग द्वारा प्रायोजित निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कोई समझौता न हो सका। 1930 के दशक के आरंभ में विश्व शांति की दिशा में रुकावट आई। लीग के पास शांतिपूर्ण समाधान अध्यारोपित करने की कोई कार्यकारी शक्ति नहीं थी। जापानी सैन्यवाद, इतालवी फासीवाद और जर्मन नाजीवाद अपनी माँगों के प्रति लगातार कड़े होते चले गए।

1931 में जापानी सेनाओं ने चीन के एक प्राकृतिक संसाधनों से युक्त क्षेत्र मंचुरिया पर कब्जा जमा लिया और इसे कठपुतली राज्य बना लिया जिसे मंचुकुओं के नाम से जाना जाता था। कुछ इतिहासकार इस घटना को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानते हैं। इस जलती आग में घी डालने का काम तब हुआ जब इतालवी सेनाओं ने एबिसिनिया (आधुनिक इथोपिया) पर आक्रमण किया और मई 1936 तक इस पर कब्जा जमा लिया। जर्मनी में हिटलर ने वर्साय की संधि शर्तों का उल्लंघन करते हुए सैन्य शक्ति बढ़ाने का कार्यक्रम बढ़े पैमाने पर शुरू किया। मार्च 1936 में उसने पश्चिमी ताकतों के सामने जर्मन वायुसेना (लुफ्तवफे) की स्थापना की घोषणा की। इसी वर्ष जर्मनी और इटली ने एक समझौता किया जिसे रोम-बर्लिन धुरी के नाम से जाना गया जिसमें 1940 में जापान भी शामिल हो गया। मार्च 1938 में जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया का संघ (*आंशुलस*) बनाने के लिए जर्मन सेना ने ऑस्ट्रिया में कदम रखा। 1938 में जर्मन भाषी लोगों के वर्चस्व वाले पश्चिमी चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र सूडेटैनलैंड पर हिटलर ने नियंत्रण स्थापित करना चाहा। ब्रिटेन किसी भी कीमत पर शांति स्थापित करने को इच्छुक था। इसके लिए वह हिटलर की माँग को मानने और तुष्टिकरण की नीति अपनाने के लिए भी तैयार था। सितम्बर 1938 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेवील चेम्बरलेन और फ्रांसीसी प्रमुख डालाडियर जर्मनी को सूडेटैनलैंड वापस करने के लिए राजी हो गए और चेकोस्लोवाकिया को यह समझौता (जिसे म्युनिख समझौते के नाम से जाना गया) मानने के लिए बाध्य किया। तुष्टिकरण की असफलता तुरंत सामने आई। हिटलर ने मार्च 1939 में म्युनिख समझौते का उल्लंघन किया और बाकी बचे चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा जमा लिया। बाद में पोलैंड के साथ भी उसने ऐसा ही किया।

स्पेन में विचारधारात्मक टकरावों के परिणामस्वरूप गृह युद्ध (1936-39) हुआ जो द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्व-अभ्यास था। 1936 में स्पेन में गणतंत्रवादियों, समाजवादियों, अराजकतावादियों और सिंडिकेलिस्टों के 'लोकप्रिय मोर्चा' ने सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया। सेनाध्यक्षों और दक्षिणपंथी दल इस मोर्चे के कार्यक्रमों से घबरा गए और उन्होंने जेनरल फ्रैंको के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस स्थिति में दुनिया की अन्य सैन्य ताकतों को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका मिला। विभाजन पूर्णतः स्पष्ट थे। फासीवादी और नाजी शासन व्यवस्थाओं ने जेनरल फ्रैंको को सैन्य समर्थन दिया जबकि सोवियत संघ ने गणतंत्रवादियों की मदद की। गणतांत्रिक ताकतों को कई देशों से 'स्वयं सेवक' भी प्राप्त हुए। हालांकि इसके बाद उदारवादी प्रजातंत्रों की इसमें प्रत्यक्ष राष्ट्रीय भागीदारी नहीं रही।

14.3 विश्व युद्धों में हिस्सा लेने वाले राष्ट्र

प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत बाल्कन क्षेत्र से हुई जहाँ अनेक राष्ट्रीयताएं आपस में उलझ रही थीं और जातीय संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था। प्रथम विश्व युद्ध इस प्रकार शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया-हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस पर और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी। 3 अगस्त को जर्मन सेना ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया और 4 अगस्त को फ्रांस पर आक्रमण हुआ। जर्मनी द्वारा बेल्जियम की तटस्थता की नीति के उल्लंघन के बाद ब्रिटेन को फ्रांस और रूस के पक्ष में युद्ध में शामिल होने का एक बहाना मिल गया। ब्रिटेन के पूरे विश्व में निजी हितों की रक्षा रूपी स्वार्थ के कारण युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया और इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और सबसे बड़ा ब्रिटिश उपनिवेश भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जिसके ब्रिटेन के साथ नजदीकी संबंध थे भी इसमें शामिल हो गया। ऑस्ट्रिया-हंगरी ने रूस पर 6 अगस्त को आक्रमण कर दिया और फ्रांस तथा ब्रिटेन ने 12 अगस्त को ऑस्ट्रिया-हंगरी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इटली ने कूटनीतिक ढंग से 1882 के त्रिपक्षीय समझौते के बाद से अपने को ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ जोड़

कर रखा और उसने 3 अगस्त को अपनी तटस्थता की घोषणा कर दी। आगे आने वाले महीनों में फ्रांस और ब्रिटेन ने उससे काफी आग्रह किया। 23 मई 1915 को इटली की सरकार मित्र राष्ट्रों के दबाव में आ गई और उसने क्षेत्रीय विस्तार के लिए ऑस्ट्रिया-हंगरी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध की तरह ही दुनिया दो सैन्य खेमों में विभक्त हो गई। कुछ बदलाव के साथ खेमे पहले की ही तरह बने रहे। केवल इटली, जापान, तुर्की, रोमानिया जैसे राज्यों ने खेमे बदले क्योंकि वे प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्राप्त क्षेत्रीय अधिकारों या विचारधारात्मक कारणों से असंतुष्ट थे। जर्मनी, इटली और जापान (धुरी राष्ट्रों) के दल में बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, अल्बानिया, फिनलैंड और थाइलैंड शामिल हो गए। मित्र राष्ट्रों के खेमे में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, बेल्जियम, डेनमार्क, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। मित्र राष्ट्रों के खेमे में अन्य राष्ट्र इस प्रकार थे– अर्जेनटिना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजिल, ग्रीस, चेकोस्लोवाकिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, नार्वे, पोलैंड आदि।

बोध प्रश्न 1

1) औद्योगीकरण ने शक्तियों के संबंधों को कैसे प्रभावित किया? 100 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

2) सैन्य गठबंधनों की व्यवस्था के कारण विश्व युद्ध का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त हुआ? लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

3) निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?

   क) सैन्य गठबंधनों की व्यवस्था सुरक्षा उद्देश्य के लिए की गई थी परंतु इससे विश्व और भी असुरक्षित हो गया।

   ख) स्पेन का गृह युद्ध उस देश का आन्तरिक मामला था।

   ग) ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई तुष्टिकरण की नीति का कोई फायदा नहीं हुआ।

   घ) प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बने सशस्त्र खेमे एक समान नहीं थे।

14.4 आपसी टकराव वाली विचारधाराओं के रूप में युद्ध

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों की क्रांतियों से आधुनिक राजनीति की शुरुआत हुई और इसे चुनावों, दलों और प्रतिनिधित्व के जरिए संस्थागत रूप प्रदान किया गया जिससे पूरा यूरोपीय समाज और राजनैतिक व्यवस्था विभिन्न विचारधाराओं में बंट गए– वामपंथी धारा, मध्यमार्गी धारा, (उदारवादी जनतांत्रिक) और दक्षिणपंथी विचारधारा (प्रति-क्रांतिकारी)। आगे आने वाले उपभागों में हम राजनैतिक परिदृश्य के सृजन और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।

14.4.1 दो विश्व युद्धों के दौरान विचारधाराओं द्वारा परिभाषित सशस्त्र खेमे

आपने देखा है कि विरोधी खेमों में विभाजन की स्थिति दोनों युद्धों में पहले की तरह ही बनी हुई थी और युद्धोन्मुख देश गठबंधनों में पहले की तरह ही विभाजित थे। ज्यादातर मामलों में इन क्षेत्रों के रूप में रेखांकित इन राज्यों का गठबंधन इनके आधारभूत गहरे राजनैतिक झुकाव पर आधारित था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका दोनों युद्धों में एक साथ मिलकर लड़े थे। उनके पास सुस्थापित उदारवादी जनतांत्रिक परम्परा थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, जापान तथा हंगरी में इस प्रकार की जनतांत्रिक परम्पराओं का अभाव था। हालांकि जापान और इटली ने प्रथम युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खेमे की सहायता की थी परंतु दोनों युद्धों के अन्तराल में उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था और वहाँ स्थापित तानाशाही और निरंकुश शासन व्यवस्थाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने से मिलती-जुलती ताकतों के साथ समझौता किया था। रोमेनोव की रूसी निरकुंश सरकार ने आर्थिक दबावों के कारण पश्चिमी जनतंत्रों को समर्थन दिया क्योंकि बाहरी निवेश में फ्रांस का हिस्सा 25% था (1914) और रूसी बैंकिंग, रेलवे विकास और दक्षिणी रूसी औद्योगिक परिसर ये सभी फ्रांसीसी पूँजी पर आश्रित थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अन्तर-युद्ध प्रत्यारोपों के बावजूद अति दक्षिणपंथी तानाशाही के खतरे के खिलाफ साम्यवादी सोवियत संघ पुनः वैचारिक दबावों के कारण पश्चिमी उदारवादी जनतंत्रों से समझौता करने पर मजबूर हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औटोमन साम्राज्य ने केंद्रीय शक्तियों को समर्थन दिया था। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जनतांत्रिक सुधारों के कारण टर्की मित्र राष्ट्रों के खेमें में शामिल हो गया।

उदारवादी जनतांत्रिक विश्व से मध्य यूरोपीय साम्राज्यों का अन्तर मात्र चुनाव, मतदान के अधिकार और संसदों के कारण ही नहीं था बल्कि वहाँ एक अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह सरकारें भी कायम थीं। फ्रांस-प्रशा युद्ध (1870) के बाद बिस्मार्क द्वारा स्थापित जर्मन साम्राज्य 'ऊपर से हुई क्रांति' का परिणाम था जिसमें प्रशा की सेना की सहायता ली गई थी। 1871 के जर्मन संविधान के द्वारा संघीय परिषद (बंडस्रैट) को औपचारिक संप्रभुता प्रदान की गई, जिसके सदस्यों को सदस्य राज्यों के कार्यकारियों द्वारा मनोनीत किया जाता था। इस संविधान के द्वारा एक प्रत्यक्ष, गुप्त, वयस्क पुरुष मताधिकार द्वारा *राइखस्टैग* या 400 सदस्यों वाली संसद की स्थापना की गई। परंतु इस व्यवस्था में संसदीय उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था क्योंकि सम्राट द्वारा नियुक्त शाही चांसलर के पास आपार शक्ति थी और वह *राइखस्टैग* के प्रति जवाबदेह नहीं था। इस प्रकार जर्मन साम्राज्य में प्रशा के सैन्य वर्चस्व और साम्राज्यिक परिसंघ का मिला-जुला रूप सामने आया जिसमें आधुनिक मतदान के साथ-साथ प्राचीन राजतंत्रीय सत्ता भी मौजूद थी। प्रभुत्वशाली प्रशा राज्य में सम्राट का निरंकुशता के तीन स्तंभों सेना, नौकरशाही और विदेशी मामलों पर नियंत्रण बना रहा। प्रशा के भूमिपति या जुंकर इस राज्य के प्रमुख स्तंभ बने रहे। जर्मन राज्य के बारे में कार्ल मार्क्स

ने कहा है कि "यह एक सैन्य निरंकुश शासन था जिसे संसदीय मुखौटा पहनाया गया था और इसमें सामंती तत्व मौजूद थे। इस पर बुर्जुआ वर्ग का प्रभाव था, नौकरशाही का नियंत्रण था और इसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त था।

इसी प्रकार ऑस्ट्रिया-हंगरी के हैब्सबर्ग राजतंत्र और औटोमन साम्राज्य पर भी मध्ययुगीन सामाजिक संस्थाओं और सैन्य तौर-तरीकों का प्रभाव था। हालांकि 1861 में ऑस्ट्रिया-हंगरी में एक संसदीय सरकार की स्थापना का स्वांग रचा गया था परंतु संसद में प्रतिनिधित्व पर नियंत्रण लगा हुआ था और इसमें पादरी वर्ग और बड़े भूमिपति वर्गों से मनोनीत सदस्यों का बाहुल्य था। 1907 में सार्वभौम वयस्क पुरुष मताधिकार लागू किया गया परंतु इससे राज्य की प्रकृति में बहुत बदलाव नहीं आया। इसी प्रकार 1908 में युवा तुर्कों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिक संसदीय सरकार की स्थापना की गई और औटोमन साम्राज्य का विघटन होने लगा। 1922 में सुल्तान मुहम्मद के शासन के समापन के तुरंत बाद ही तुर्की में जनतांत्रिक सुधार हुआ और जनतांत्रिक नीतियां सामने आईं।

युद्ध के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी का पक्ष लेना पड़ा। लाखों लोगों के लिए यह अस्तित्व की पहचान का प्रश्न बन गया। बाहरी शत्रु का सामना करने के लिए आंतरिक, वैचारिक मतभेदों को भुला दिया गया। युद्ध के कारण वैचारिक प्रचार या प्रभुत्व पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इसने क्षेत्रीय रूप से रेखांकित राज्यों के नागरिकों में एकता लाने का प्रयत्न किया। युद्ध, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और शत्रु राष्ट्रों की निंदा के रूप में यह एकता का दृष्टिकोण पूरी तरह उभर कर सामने आया। हालांकि अस्तित्व की पहचान की यह प्रक्रिया निर्विघ्न और आसानी से सुलझने वाली प्रक्रिया नहीं थी। उदाहरण के लिए, जर्मन संसद में सैकड़ों ऐसे समाजवादी सदस्य थे जो वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के प्रति समर्पित थे। परंतु केवल कार्ल लिबकनेख्त ने अकेले 1914 में युद्ध के लिए, लिए जाने वाले ऋणों का विरोध किया था। ब्रिटिश लेबर पार्टी के शांतिप्रिय नेता ज्योर्ज लांसबरी को इसलिए दल के नेतृत्व से हटा दिया गया क्योंकि वे ब्रिटेन के बड़े पैमाने पर फिर से सैन्यीकरण के विरोधी थे।

14.4.2 युद्ध की शुरुआत के समय यूरोप का राजनैतिक परिदृश्य

इस विभाजन के वामपंथी हिस्से मुख्य रूप से समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। 1864 में अन्तर्राष्ट्रीय कामगार पुरुष संघ या प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय का जन्म हुआ। हालांकि अपने आंतरिक अन्तर्विरोधों को न सुलझा पाने के कारण 1876 में यह ध्वस्त हो गया परंतु मुख्यतः राष्ट्रीय आधारों पर संगठित समाजवादी और सामाजिक जनतांत्रिक दलों को इसने जन्म दिया। 1875 में सार्वभौम जर्मन कामगार पुरुष संघ का विलय मार्क्सवादी समूह में हुआ और परिणामस्वरूप जर्मन समाजवादी जनतांत्रिक दल का उदय हुआ। 1878-90 में बिस्मार्क द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद इसका प्रभाव बढ़ा। 1872 में लोकप्रिय मत में इसका हिस्स 3.2% था जो 1912 में बढ़कर 34.8% हो गया। 1879 में जूल्स गेस्डे ने फ्रांस में समाजवादी दल की स्थापना की। 1890 के दशक में फ्रांस में पाँच समाजवादी दल थे। जेन ज्योर्स का स्वतंत्र समाजवादी दल (1893) इनमें प्रमुख था। 1905 में दोनों प्रमुख समाजवादी दल आपस में मिल गए और फ्रेंच चेम्बर ऑफ डेपुटिज में समाजवादी प्रतिनिधियों की संख्या 1906 में 52 से बढ़कर 1914 में 102 हो गई। ब्रिटेन में 1884 में समाजवाद का प्रचार करने के लिए फेबियन सोसाइटी की स्थापना की गई। बाद में 1893 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना हुई जो संसदीय तरीकों द्वारा समाजवाद लाना चाहती थी। 1900 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके सदस्यों की संख्या मात्र 2 थी तो 1910 में बढ़कर 42 हो गई। 1880 के दशक के बाद इसी प्रकार इटली, रूस, हंगरी, बेल्जियम, स्वीडेन, स्विटजरलैंड आदि में

समाजवादी-जनतांत्रिक दलों की स्थापना हुई। 1889 में राष्ट्रीय समाजवादी दलों के एक लचीले परिसंघ के रूप में दूसरे समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। इसमें मार्क्सवादियों के नेतृत्व में उग्र वामपंथी और सुधारवादी शाखा थी जो मौजूदा संस्थाओं और सामाजिक संरचना के भीतर उदारवादी जनतांत्रिक राज्य और दलों से समझौता कर मजदूरों की स्थिति सुधारना चाहती थी।

इसी प्रकार उदारवादी जनतांत्रिक दल अपने–अपने देशों में औद्योगिक पूँजीवाद को बढ़ावा देने की मध्यमार्गी राजनीति का प्रतिनिधि करते थे। फ्रांस के तीसरे गणतंत्र के गणतंत्रवादियों, ब्रिटेन में विग या उदारवादी दल, जर्मनी में उदारवादी दल और कैथोलिक सेंटर पार्टी तथा इटली में कैथोलिक पिपुल्स पार्टी तथा रूस में कैडेट पार्टी मध्यमार्गी राजनीति के ही उदाहरण थे। फ्रांसीसी लेजिटिमिस्ट, जो फ्रांस में राजतंत्र की पुनः स्थापना करना चाहते थे, ब्रिटेन में टोरी या रूढ़िवादी, जर्मनी में कृषि लीग और जर्मन कामगार पार्टी (1903 में स्थापित डी. ए. पी.) दक्षिणपंथी राजनीति के प्रमुख उदाहरण थे। ऑस्ट्रिया में *हेमवर*, फ्रांस में ऐक्शन फ्रांसेस (1899 में स्थापित), इतालवी राष्ट्रवादी संघ (या 1910 में स्थापित एएनआइ) और फ्रांस में अतिराष्ट्रवादी बोलंगाववादी जैसी बीसवीं शताब्दी की कुछ अर्द्ध-सैन्य ताकतें अति दक्षिणपंथी संस्थाएं थीं।

युद्ध के बाद केंद्रीय यूरोपीय साम्राज्यों पर उदारवादी जनतंत्रों ने अपना नियंत्रण पुनः स्थापित किया। कई मामलों में सुधारवादी और समझौतापसंद समाजवादी नेताओं ने इसमें सहायता की। हालांकि फासीवादी और दक्षिणपंथी तानाशाहों ने आर्थिक समस्याओं से जुड़े अतिवादी राष्ट्रवादी नारों का सहारा लिया और इसके परिणामस्वरूप इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, पोलैंड, स्पेन और जापान जैसे देशों में शक्तिशाली दक्षिणपंथी सैन्य संगठन बनने की गति तेज हुई। जनतांत्रिक संस्थाओं की परम्पराओं से रहित देशों में खासतौर पर इस प्रकार की तानाशाही व्यवस्थाओं का उद्‌भव हुआ। उदारवादी जनतांत्रिकी की अवधारणा की तहत राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए था जबकि इन विभिन्न तानाशाही व्यवस्थाओं में राज्य की सर्वोच्चता ही मूल सिद्धांत थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका आदि जैसे उदारवादी प्रजातंत्र और साम्यवादी सोवियत संघ दक्षिणपंथी तानाशाही को समाप्त करने के लिए एकजुट हुए। इसके परिणामस्वरूप 1945 में दो सशस्त्र खेमों की स्थापना हुई – पश्चिमी जनतांत्रिक खेमा और साम्यवादी खेमा जिनके विचार एक दूसरे से अलग थे परंतु उनका उद्देश्य एक था अर्थात विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करना।

14.5 शीत युद्ध की शुरुआत

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व साम्यवादी खेमे और गैर-साम्यवादी खेमे में विभक्त हो गया और बहुत थोड़े से राज्य इससे तटस्थ रह सके। फरवरी 1945 में चर्चिल (ब्रिटिश प्रधानमंत्री), रूजवेल्ट (अमेरिकी राष्ट्रपति) और सोवियत संघ के नेता स्टालिन की बैठक क्रीमिया में याल्टा में हुई। जर्मनी और जापान को परास्त करने के उद्देश्यों पर सहमत होना मित्र राष्ट्रों के लिए आसान था। परंतु जैसे ही भविष्य का प्रश्न सामने आया हितों, विचारों और दृष्टिकोणों का मतभेद उभर कर सामने आ गया। ब्रिटेन और अमेरिका साम्यवाद को नापसंद करते थे और उन्हें इसके यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने का डर था। युद्ध के दौरान रूसी शक्ति प्रदर्शन से भी वे सतर्क हो गए थे। मित्र राष्ट्र पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, युगोस्लाविया और अल्बिनिया जैसे पूर्व यूरोपीय देशों में "लाल सेना" के हटने के बाद निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार हो गए। परंतु

स्टालिन ने इन देशों में साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दीं। स्टालिन ने जर्मन सिलेसिया के बदले में पूर्वी पोलैंड पर अधिकार प्राप्त कर लिया और इसके बाद रूसी प्रभाव वाली सीमा पश्चिम दिशा में और आगे बढ़ा ली गई। ब्रिटेन ने ग्रीस में हस्तक्षेप किया और वहाँ स्थापित साम्यवादी सरकार को गिरा दिया। आरंभ में जर्मनी चार क्षेत्रों में विभाजित था। रूसी नियंत्रित क्षेत्र में स्थित राजधानी शहर बर्लिन भी इसी प्रकार विभाजित था। 1948 में तीन पश्चिमी क्षेत्रों ने पूर्वी क्षेत्रों से सलाह किए बिना एक नई मुद्रा जारी कर दी जिसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ ने आठ महीनों तक रेल और रोड यातायात को अवरुद्ध रखा और इस दौरान ब्रिटेन तथा अमेरिका ने बर्लिन में सभी समान हवाई जहाज से पहुँचाया। एक तरफ सोवियत रूस था दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस। हर मामले में ये एक दूसरे का विरोध करते थे। सोवियत नेतृत्व में पूर्वी यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना के लिए मार्शल योजना के तहत अमेरिकी सहायता प्राप्त करने से इनकार कर दिया। 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाया और माहौल इतना विद्वेषपूर्ण हो गया कि इसे शीत युद्ध कहा गया। प्रत्यक्ष रूप में शांति बनी रही पर परदे के पीछे विचारधारात्मक तनाव बना रहा और अनेक बार इन महाशक्ति खेमों की ओर से सैन्य कार्रवाई किए जाने या परमाणु बम के उपयोग की धमकी दी जाती रही।

बोध प्रश्न 2

1) विश्व युद्धों के सैन्य खेमे आपसी विचारधारात्मक मतभेदों से जूझ रहे थे। लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी कीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

....

2) शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? 10 पंक्तियों में समझाइए।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

14.6 सारांश

इस इकाई में आपने यह देखा की पश्चिमी देशों में औद्योगीकरण होने से दुनिया पर सर्वोच्चता का दावा करने वाले कई दावेदार सामने आए। ऐसी किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अभाव था जहाँ इन दावों को मध्यस्थता और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता था। इसलिए पूरी दुनिया में सशस्त्र टकराव होना अवश्यंभावी हो गया था। हमने यह भी देखा कि 19वीं शताब्दी में वैचारिक स्तर पर यूरोप तीन हिस्सों में बंट गया था और इसके कारण इनके सुपरिभाषित सैन्य खेमे भी बने। इसलिए हम यह भी देखते हैं कि दोनों विश्व युद्धों में हिस्सा लेने वाले देश जिन खेमों में बंटे थे, वे उद्देश्य प्राप्ति संदर्भ में एक समान थे। 1914 में शुरू हुआ युद्ध लम्बे समय तक चला। 1919 और 39 के बीच इसमें एक लम्बा अन्तराल आया। इस दौरान इतिहास के रंगमंच पर कई उतार-चढ़ाव आए और अन्ततः उदारवादी जनतंत्र और समाजवाद के गठबंधन ने दक्षिणपंथी प्रति-क्रांतिकारी खेमे को नष्ट कर दिया। इस प्रबल संघर्ष के बावजूद शांति स्थापित न हो सकी और एक अप्रत्यक्ष तथा विचारधारात्मक विद्वेष का युग शुरू हुआ जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1945 के बाद से दुनिया दो खेमे में बंट गई। एक में पश्चिमी उदारवादी जनतांत्रिक देश थे और दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी खेमा।

14.7 शब्दावली

एंशुलस : जर्मन संघ और ऑस्ट्रिया की अखिल जर्मन विचारधारा के संदर्भ में प्रयुक्त संघ के लिए जर्मन शब्द।

तुष्टिकरण : नाजी सरकार की आक्रामक नीतियों को कम करने के लिए उसकी माँग को पूरा करने की नीति।

लैबेन्सरॉम : नाजियों की एक विचारधारा जो जर्मन प्रजाति को एक विशिष्ट सर्वोच्च स्थान देना चाहते थे।

लामबंदी : लड़ाई के लिए सेना जुटाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द।

राष्ट्रीय आत्म निर्धारण : किसी राष्ट्रीयता को अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार।

हर्जाना : युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई।

14.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) देखिए उपभाग 14.2.1 और 14.2.2

2) देखिए भाग 14.3

3) क) सही ख) गलत ग) सही घ) गलत

बोध प्रश्न 2

1) उपभाग 14.4.2 को संक्षेप में लिखें

2) देखिए भाग 14.5

कुछ उपयोगी पुस्तकें

George Rude: *Revolutionary Europe,*

E. J. Hobsbawm: *The Age of Revolution, 1789-1848*

William Doyle: *The Oxford History of the French Revolution*

Martyn Lyons: *Post-revolutionary Europe, 1815-1856*

E. J. Hobsbawm: *The Age of Capital, 1848-1875*

E. J. Hobsbawm: *The Age of Empire, 1875-1914*

Tom Kemp: *Industrialization in nineteenth Century Europe*

C. A. Bayly, *The Birth of the Modern World, 1780-1914*

E. J. Hobsbawm: *Nation and Nationalism since 1780: programme, Myth, Reality*

E. H. Carr: *The Russian Revolution From Lenin to Stalin, 1917-21*

Sheila Sitzpatrick: *The Russian Revolution*

A . J. P. Taylor, *The Origins of the Second World War.*

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

NOTES

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY